

Vol II Issue XI Dec 2012

ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor

Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief

H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya [Malaysia]	Catalina Neculai University of Coventry, UK	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Horia Patrascu Spiru Haret University, Bucharest, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA Nawab Ali Khan College of Business Administration
Titus Pop	George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher	

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University, Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yaliker Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust),Meerut	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra
	Sonal Singh	

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net**



मानवाधिकारों के प्रति जन-जागरूकता में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण

उमा त्रिपाठी,¹ धीरेन्द्र पाठक,² धरवेश कठेरिया, शिवांजलि कठेरिया, संदीप कुमार वर्मा, तेज बहादुर यादव⁶

¹प्रोफेसर, संचार अध्ययन एवं शोध विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

²रीडर, संचार अध्ययन एवं शोध विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

³सहायक प्रोफेसर, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)।

⁴स्वतंत्र लेखक एवं शोध कार्य में संलग्न, वर्धा (महाराष्ट्र)।

⁵सहायक प्रोफेसर, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)।

⁶वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

सारांश :

समाज, राज्य और राष्ट्र मानवाधिकार संरक्षण के मुद्दे पर एक नहीं होते हैं। क्योंकि यह विषय प्रत्येक समाज में अपने मायने बदल लेता है। एक संस्था में जहां काम करने वाले कर्मचारी के लिए अधिक काम करना मानवाधिकारों का हनन होगा, तो उस संस्था के मालिक के लिए यह कार्य लाभकारी होगा। प्रायः अधिकतर खबरों में मानव अधिकार से संबंधित तथ्यों को शामिल किया जाता है। परंतु अधिकांश मामले जो राज्य या पुलिस प्रशासन द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी होते हैं, उन्हें सरकारी मीडिया पूरी स्पष्टता के साथ सामने नहीं लाता है। प्राइवेट मीडिया ऐसी घटनाओं पर अधिक सक्रियता से भूमिका निभाता है। विभिन्न जनमाध्यमों जैसे— फिल्म, धारावाहिक, विज्ञापन, चेतानवी, सूचनाओं इत्यादि द्वारा मानवाधिकारों संबंधी घटनाओं को सामाजिक धरातल पर रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को मीडिया की नजर देखने का प्रयास किया गया है। इस शोध में मानवाधिकार संरक्षण में राज्य और जनसंचार माध्यमों के बीच के आपसी तालमेल का भी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना:

संचार और समाज के सामन्जस्य को प्रायः अंतर्संबंधी देखा गया है और इन अंतर्संबंधी ताने-बाने के द्वारा ही समाज और सम्मिलित व्यक्तियों के समग्र विकास के आधार निर्मित होते हैं। समाज की जटिल व्यवस्था के साथ मानव अधिकारों को स्थापित करने की प्रक्रिया को देखा जाए तो मानव अधिकार जैसी संकल्पना समाज की संरचना के साथ उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि, समाज उत्पत्ति की व्याख्या हेतु विभिन्न दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सत्तात्मक सिद्धांत आदि प्रचलन में आए। जिसमें एकता की भावना, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता की आवश्यकता ने मनुष्य को सामाजिक बनने की अनुभूति दिलायी। इस क्रम में ही अनेक संस्कृतियों के जन्म हुए जिनका विस्तार समय के साथ आगे ले जाने का कार्य जनमाध्यमों ने किया। जनमाध्यम किसी व्यक्ति, छोटी इकाई, सहित सामूहिक व्यवस्था को स्थापित करने के प्रतीक रूप में देखे जा सकते हैं। व्यवस्था से तात्पर्य बुद्धि, तर्क, संस्कृति जैसे प्रयत्न होते हैं जिन्हें सहेजना, संप्रेषित व संस्कृति के संवाहक रूपी कार्य विभिन्न जनमाध्यमों ने किये हैं। परंतु सामूहिकता के साथ सार्वभौमिकता की चुनौती आज भी समाज में बड़ी चुनौती है। अनेक राज्यों में मनुष्यता को स्थापित करने की कवायद को महत्ता देना और सभी समुदाय, समाज, वर्ग आदि को संतुलन देने के साथ उन्नत की सहमति को सार्वभौमिक व्यवहार और व्यवस्था में लाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरत है। समाज और सार्वभौमिकता के बीच मानव ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे सभ्य राष्ट्र में राज्य और सरकारों द्वारा संरक्षित करना शक्ति संरचना से अधिक आधारमूलक है। मानव को मानवीयता संबंधी उपागम निर्मित करना मानववाद है। मानववाद को स्थापित करने के लिए मानवाधिकारों के आयाम को विस्तृत करना आवश्यक है। वहीं मानवाधिकारों के संरक्षण और विस्तार के लिए जनमाध्यम एक अति महत्वपूर्ण युक्ति है। जनमाध्यमों द्वारा इस दृष्टिकोण को गति दी जा सकती है।

प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के अलावा यूनान और रोम के दार्शनिकों ने मानवाधिकार जैसे अधिकारों के संबंध में संरक्षण की चर्चा की, लेकिन उनके आधार धर्म के अधार थे। वहीं इसके इतिहास को देखें तो इंग्लैण्ड के सम्राट जॉन द्वारा 15 जून 1215 में अंग्रेज सामंतों को एक आदेश जिसे मैग्नाकार्टा अथवा मैग्नाचार्टा के द्वारा प्रदत्त किया गया। इस चार्टर में इस बात को स्थापित किया गया था कि प्रजा और समुदाय के अधिकारों को संरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सम्राट को दायित्वधारी घोषित किया गया, जिसके लिए बाध्यता भी शामिल रही। वहीं प्रजा के प्रति किसी व्यक्ति को अधिकार के अनुपालन में यदि कोई असफल होता पाया गया तो बलपूर्वक अधिकारों के पालन की बाध्यता रहेगी और उसे विवश किया जाएगा।

मानव अधिकार की संकल्पना में मानव होने के लिए अनेक गरिमामय हित की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। दूसरी ओर इस विचारधारा का मूल उद्देश्य सामाजिक बुराईयों और शोषण के विरुद्ध स्वस्थ परिवेश का निर्माण करना है। चौदहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी के बीच सामंतवाद और मध्ययुगीन धर्म के विरोध में आधुनिक मानववाद का जन्म एक विशिष्ट वैचारिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था। मानव अधिकार के पक्षधर विद्वान दांते, पैट्रॉक, ब्रूनो, मातेन, कार्पिनिकस, बेकन आदि प्रमुख रूप थे और इनका मानना था कि संपूर्ण मानव का सामाजिक दायित्व है कि व्यक्ति को व्यक्ति की दशा सुधारने में मदद करनी चाहिए। इस स्वतंत्र विचारधारा का संचार और प्रसार विश्व-स्तर पर हुआ, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन और धार्मिक बंधनों का विरोध किया गया। दुनिया के संचारकों द्वारा जनमाध्यमों के मदद से इन विचारों को धारणा बनाने की शुरुआत की जाने लगी। और परिणामतः लोगों में किए गए संचार का असर दिखा, दुनिया भर में लोगों ने धर्म को तिरस्कार किया, क्योंकि धर्म में मानव की अपेक्षा ईश्वर को अधिक महत्व दिया जाता है। मार्क्स ने भी अपने लेखों में मानववाद की

Title: मानवाधिकारों के प्रति जन-जागरूकता में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण

Source: Indian Streams Research Journal [2230-7850] उमा त्रिपाठी, धीरेन्द्र पाठक, धरवेश कठेरिया, शिवांजलि कठेरिया, संदीप कुमार वर्मा, तेज बहादुर यादव/yr:2012 vol:2 iss:11

हिमायत की, और कहा कि मानव के हितों और गरिमा की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।

मानवाधिकारों को जिस प्रकार से दो प्रमुख भागों में देखा जाता है, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहले अधिकारों में सिविल और राजनैतिक अधिकार जिनमें व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, एकांतता, गृह एवं पत्राचार, संपत्ति के अधिकार, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से स्वतंत्रता, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता, विचार, अंतरात्मा एवं धर्म तथा आवागमन जैसी स्वतंत्रता शामिल हैं। वहीं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अधिकार में इसके सभी पक्षों की भागीदारी के अधिकार शामिल हैं। इनमें पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के समुचित स्तर तथा भूख से स्वतंत्रता, कार्य एवं व्यवसाय के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार तथा शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को इन अधिकारों की कोटि में शामिल किया गया है। इन दोनों प्रकार के अधिकार व्यक्ति को गरिमायुक्त जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अतः इन अधिकारों को किसी भी स्थिति में आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए है।

आधुनिक तर्क के अनुसार यदि मानव अधिकारों को देखा जाए तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इस संकल्पना का सही विस्तार संचार माध्यमों के बिना संभव नहीं है क्योंकि संचार माध्यम मन मस्तिष्क पर अपनी छवि छोड़ने में अधिक कारगर होते हैं। मानव अधिकार संबंधी वैश्विक-स्तर पर अनेक प्रयासों को सार्थक करने में जनमाध्यम एक विचार स्थापित करने का काम करते हैं। राज्यों के कानून मानवाधिकार संरक्षण के लिए दायित्व रखने में कितने सक्षम हैं और उन्हें किन-किन क्षेत्रों में विस्तार लाने की आवश्यकता है। वहीं मानवाधिकार की संकल्पना की स्थापना द्वारा समाज और व्यक्ति के समग्र विकास संबंधी पहलुओं को मीडिया समय-समय पर प्रत्येक स्तर पर सामने लाने का काम कर रही है। इसलिए जनमाध्यमों की स्थिति मानवाधिकारों को स्थापित करने में अधिक महत्वपूर्ण साबित हो रही है। राज्य के अनेक उत्तरदायित्वों को मीडिया उजागर करती है। भारत जैसे देश की बात की जाए तो अभी मानवाधिकार की संकल्पना को औसत रूप में ही देखा जा सकता है। जहां राज्य द्वारा अनेक स्तर पर इन अधिकारों को लिखित और कानूनी रूप प्रदान किया गया है। परंतु जिन व्यक्तियों द्वारा इन्हें संचालित किया जाना है, प्रायः उनके द्वारा ही इन अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जाति और वर्ग आधारित समाज भी भारत में मानवाधिकारों की विडंबना है। ऐसे में जनमाध्यम ही एक प्रमुख विकल्प है जिन्हें विधियों के अनुकरण में सहायक बनाया जा सकता है।

जनमाध्यम मानवाधिकार सहित किसी भी चेतना के विस्तार में प्रबल रहे हैं। दुनिया की अधिकांश परिवर्तनकारी स्थितियों के लिए चेतना जगाने का कार्य भी अलग-अलग स्तर पर मास कम्युनिकेटर, स्लोगन, पोस्टर, शिल्पकारी, रैली, मेले, प्रदर्शनी, स्मृति स्थल, स्तूप, प्रेरक लेख आदि ने किया है। वर्तमान समय में भी इन जनमाध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही नए जनमाध्यमों का भी विस्तार हुआ है। न्यू मीडिया ने विश्व स्तर पर एक प्लेटफॉर्म पर लोगों की सहभागिता बनाए जाने का माध्यम सिद्ध कर दिखाया है। ऐसे में मानवाधिकार संबंधी चेतना का कार्य तथा उल्लंघन में आलोचना एवं पीड़ित के लिए मार्गदर्शन सहित जनमत निर्माण में भी न्यू मीडिया बतौर जनमाध्यम लोकप्रिय साबित हुआ है। लोगों में आमतौर पर मानवाधिकारों संबंधी जागरूकता की कमी को भी जनमाध्यम लगातार उजागर करते आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, किसी समाचारपत्र की खबर या किसी चैनल पर चर्चा का विषय आदि, सभी माध्यम मानवाधिकारों को सर्वव्यापी बनाने के लिए आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए सामूहिक स्तर पर सोशल मीडिया की अंतर्वस्तु का शेयर, लिंक, सुझाव, टिप्पणी, प्रतिक्रिया जैसे कार्य भी कहीं न कहीं लोगों में चेतना बढ़ा रहे हैं।

हम रोजमर्रा जीवन की घटनाओं में देख सकते हैं, पुलिस की पिटाई, पंचायतों के अमानवीय फरमान, प्रथाओं में बर्बर स्थित का शामिल होना, फैंक्टोरियों में बाल मजदूर, महिलाओं व मजदूरों के प्रति अमानवीय व्यवहार सहित अनेक घटनाओं से लोग रूबरू हो रहे हैं। जनमाध्यमों के द्वारा ही काफी हद तक इन मामलों को सामने लाया जा सका है। अन्यथा राज्य स्वयं ही पूर्ण रूप से मानवाधिकारों को स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग के सचिव मुक्तेश वार्णाय मानते हैं कि 'सम्मानजनक जीवन का अधिकार ही मानवाधिकार है।' इन अधिकारों की रक्षा के लिए जनचेतना बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 'मानवाधिकारों के लिए व्यवस्था या पुलिस पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। ऐसे में इनके विस्तार की उम्मीद बिना जनमाध्यमों के अधूरी है।'

जनमाध्यमों की भूमिका और मानवाधिकार:

मानवाधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर मानवाधिकारों के अनुपालन संबंधी निर्देश व्याख्यायित किये हैं। वहीं संबंधित मुद्दों को जनमाध्यम भी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य सजगता के साथ करते रहते हैं। मानवाधिकारों में शामिल भोजन का अधिकार, बाल-विवाह, बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा, महिलाओं और बच्चों के गैरकानूनी व्यापार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिला यात्रियों के साथ उत्पीड़न, सेक्स के लिए महिलाओं की तस्करी, बेसहारा औरतों, व्यक्तियों के पुनर्वास, दलित एवं आदिवासियों का उत्पीड़न, खानाबदोष जनजातियों के मुद्दे, शारीरिक अक्षम लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उत्थान, दुर्घटना एवं आपदाओं में निगरानी व राहत कार्य जैसे अतिमहत्वपूर्ण व संवेदनशील मुद्दों पर जनमाध्यमों की भूमिका सामाजिक-स्तर पर न्याय दिलाने की रही है। जनमाध्यमों द्वारा पीड़ितों को सहानुभूति एवं उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ने का संबल मिलता है, वहीं कानून और व्यवस्था नियंत्रण करने के लिए दबाव रहता है। इस प्रकार जनमाध्यमों की भूमिका मानवाधिकार संबंधी घटनाओं के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्य बनाने में सहायक सिद्ध होती है। दुनिया भर में मानवाधिकार संबंधी चर्चा में यह कहा गया है कि राज्यों का दायित्व है कि वह नैतिक रूप से मानवाधिकारों का संरक्षण करें। साथ ही इससे संबंधित अभियानों में लोगों को जोड़े।

मानवाधिकार के संबंध में जनमाध्यमों का योगदान सराहनीय रहा है क्योंकि पेय जल व स्वच्छ वातावरण को वर्ष 2010 में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मानव अधिकारों की रक्षा तथा भेदभाव मिटाने के लिए लड़ाई लड़ी। इस दिवस का उद्देश्य एक ऐसी नई पीढ़ी को प्रेरित करना भी है जो मानवाधिकारों की रक्षा एवं भेदभाव मिटाने के लिए दुनिया भर में आगे आए। हालांकि दुनियाभर की सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे इन लोगों को सुरक्षा दें तथा समाज से भेदभाव मिटाने के इनके अभियान को संरक्षण दे। इस काम में जनमाध्यम आम जनता के बीच मानवाधिकारों के प्रति सजगता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

सीमाएं:

मानवाधिकार वर्तमान समय में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र इन अधिकारों को संरक्षित करने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस सफलता की आस की जाती है वह अभी तक संभव नहीं हो पा रही है। यह एक गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है। मानवाधिकार के प्रचार-प्रसार से लेकर मीडिया समय-समय पर मानवाधिकार हनन के मुद्दों को स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल तक उठाती रहती है। मानवाधिकारों को लेकर मीडिया एक सजग प्रहरी की भूमिका निभा रही है। मानवाधिकार हनन, प्रचार-प्रसार और राज्य के दायित्वों के बीच जनसंचार माध्यम कैसे सकारात्मक पहलुओं के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहा है, इस अध्ययन में ऐसे ही तत्वों को

विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

सुझाव:

मानवाधिकारों के लिए संघर्ष की गाथा आज कोई नई नहीं है। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए आदिम सभ्यता से आवाजें उठती रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं राज्य इन अधिकारों का संरक्षण करने में लचीला व्यवहार करता नजर आते हैं। उसका ये लचीला व्यवहार यह साबित करता है कि अब भी शासन व्यवस्था को संचालित करने में मानवाधिकारों का हनन होना स्वाभाविक है। मानवाधिकारों और जनसंचार माध्यमों के बीच आपसी तालमेल और संरक्षण के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं जो मानवाधिकार संरक्षण में सहायक होंगे।

- ✍ मानव सभ्यता के इतिहास में ये दर्ज है कि मानवाधिकारों का हनन मानव ही करते आए हैं। यह किसी कानून के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह तो कानून के दुरुपयोग है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए, समाज कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए।
- ✍ राज्य सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए कि वे मानवाधिकारों के हनन संबंधी मामलों में गंभीरता से कार्य करें।
- ✍ जनसंचार माध्यम केवल अपनी सकारात्मक भूमिका के बल पर ही मानवाधिकार संबंधी समाचारों का प्रसारण करते हैं, जबकि राज्य सरकार उनके इस कार्य को व्यवस्था-विरोधी मानकर ध्यान नहीं देती है, इस कार्य के लिए दोनों को मिलकर पहल करनी चाहिए।
- ✍ राज्य और मीडिया को समय-समय पर अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रचार-प्रसार करते रहना चाहिए न कि केवल मानवाधिकार दिवस के अवसर पर।
- ✍ राज्य के साथ मीडिया भी इस जिम्मेदारी को उठाए कि प्रत्येक संस्था में मानवाधिकार संरक्षण और प्रचार-प्रसार के पर्याप्त साधन और संसाधन मौजूद रहें।
- ✍ यह समस्या ग्लोबल है अतः इनके संबंध में राज्य के प्रत्येक नागरिक को जानकारी होना आवश्यक है। जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।

मानवाधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में सन् 1993 में वियना के मानव अधिकार सम्मेलन में घोषित किया गया। इस घोषणा के अनुसार सभी व्यक्ति मानवाधिकार की गरिमा और अंतर्निहित योग्यता से प्रतिभूत होते हैं। व्यक्ति और मानवाधिकार के साथ मूल स्वतंत्रता केंद्रीय विषय है। भारत जैसे देश में मानवाधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए, भारतीय संविधान में विधि के साथ स्थापित करते हुए विभिन्न अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वचित किया गया है। साथ ही संविधान की उद्देशिका के विस्तृत अर्थ में भी मानवाधिकार से जुड़े आयाम स्पष्ट होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व में स्थापित मानवाधिकार के अनुसार हैं तथा मानवीय गरिमा के साथ व्यक्ति को मान्यता देना आज के वैश्विक परिवेश में महानतम उपलब्धि है। क्योंकि इस उपलब्धि को व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है। आज विभिन्न जनमाध्यम तत्परता के साथ स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों को प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

संदर्भ:

1. प्रो. विपिन चंद्रा, आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता, प्रकाशक- हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय- दिल्ली, 1996.
2. चतुर्वेदी जगदीश्वर, माध्यम साम्राज्यवाद, प्रकाशक- अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रा.लि., नई दिल्ली, 2002.
3. सुधीश पचौरी, टेलीविजन समीक्षा: सिद्धांत और व्यवहार, प्रकाशक- वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
4. सुधीश पचौरी, उत्तर आधुनिक मीडिया विमर्श, प्रकाशक- वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
5. आनंद मित्रा, टेलीविजन एण्ड पापुलर कल्चर इन इंडिया, प्रकाशक- सेज पब्लिकेशन, दिल्ली, 1993.
6. रॉबर्ट डब्ल्यू मैक्वेसनी, इलेन मिकॉसिस बुड, जॉन बेलेमी फॉस्टर (संपादक), राजेंद्र शर्मा (अनुवादक), पूंजीवाद और सूचना का युग, (भूमण्डलीय संचार क्रांति की राजनीतिक अर्थ व्यवस्था), प्रकाशक- ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली, 2006.
7. सीन मैकब्राइड, मेनी वायसेज, वन वर्ल्ड, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी टुडे एंड टुमोरो, प्रकाशक- यूनेस्को, पेरिस, 1980.
8. जोशी रामशरण (संपादक), मीडिया और बाजारवाद, प्रकाशक- राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जगतपुरी, दिल्ली, 2002.
9. रेमण्ड विलियंस, सत्यम वर्मा, प्रमोद झा (अनुवादक), संचार माध्यमों का वर्ग चरित्र, प्रकाशक- ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली, 2000.
10. राधेश्याम शर्मा, जनसंचार, (तृतीय संस्करण), प्रकाशक- हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, हरियाणा, 1999.
11. शंभुनाथ, आज का मीडिया-समकालीन सृजन, प्रकाशक- वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2000.
12. गोपाल सक्सेना, टेलीविजन इन इंडिया-चेंज एण्ड चैलेंज, प्रकाशक- विकास पब्लिकेशन, दिल्ली, 1996.
13. मोहनदास गांधी, इंडिया ऑफ माइ ड्रींस, प्रकाशक- नवजीवन पब्लिसिंग हाउस, अहमदाबाद, 1947.
14. हंस, टेलीविजन विशेषांक, जनवरी, प्रकाशक- अक्षर प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2001.
15. नया ज्ञानोदय (मीडिया विशेषांक, अंक-83), जनवरी, प्रकाशक- भारतीय ज्ञानपीठ, 2010.
16. इम्पैक्ट, प्रकाशक- एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप पब्लिकेशन, मुंबई।
17. दीवान-ए-सराय 01, मीडिया विमर्श: प्रकाशक- सराय: नव संचार पहल, विकासशील समाज अध्ययन पीठ का कार्यक्रम, दिल्ली, 2002.
18. योजना, प्रकाशक- प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
19. विदुर (हिंदी एवं अंग्रेजी), प्रकाशक- प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिल्ली।
20. भारत, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2009, 2010, 2011.

वेबसाइट:

1. www. mediaresearch.com tvnet.com
2. www. cable.quest.com

मानवाधिकारों के प्रति जन-जागरूकता में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण



3. www.exchange4media.com
4. www.publicationdivision.nic.in
5. www.tvguide.com
6. www.tvchakra.com
7. www.tv4india.com
8. www.deloitte.com/in
9. www.mediaimpact.org
10. www.tvguide.com
11. www.indiantelevision.com

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- ✍ International Scientific Journal Consortium Scientific
- ✍ OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- ✍ Google Scholar
- ✍ EBSCO
- ✍ DOAJ
- ✍ Index Copernicus
- ✍ Publication Index
- ✍ Academic Journal Database
- ✍ Contemporary Research Index
- ✍ Academic Paper Databse
- ✍ Digital Journals Database
- ✍ Current Index to Scholarly Journals
- ✍ Elite Scientific Journal Archive
- ✍ Directory Of Academic Resources
- ✍ Scholar Journal Index
- ✍ Recent Science Index
- ✍ Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net